राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

श्री लालकृष्ण आडवाणी, नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य

मूल्य वृद्धि के विरोध में 24 अप्रैल 2008 को राजग सांसदों द्वारा संसद के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाने के अवसर पर

करोड़ों गरीब भारतीयों के जीवन–जीने के अधिकार को खतरे में डालने के लिए संप्रग सरकार जिम्मेदार

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों ने आज आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की तीव्र मूल्य वृद्धि को रोकने में संप्रग सरकार की घोर विफलता के विरोध में संसद भवन की मुख्य इमारत के चारो तरफ मानव श्रृंखला आयोजित की। यह विरोध अभियान मूल्य वृद्धि के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन का एक हिस्सा है।

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार, जो अगले महीने चार साल पूरा कर रही है, सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है। हालांकि सबसे घोर विफलता उस क्षेत्र में हुई है, जो आम आदमी को रोजाना प्रभावित करता है, मसलन–आवश्यक वस्तुओं के दामों व सेवाओं क्षेत्र में मूल्य वृद्धि। अनाजों, दालों, सब्जियों, खाद्य तेलों, चीनी, दूध, फल व मांस की कीमतों में तीव्र वृद्धि ने गरीबों के साथ–साथ मध्य वर्ग के परिवारों का भी घरेलू बजट बुरी तरह से बिगाड़ रखा है।

इसने गरीब, जिन्हें पहले से ही पोषक तत्व काफी कम मिल पाता है, को और भी कम खाने के लिए मजबूर कर दिया है। यही नहीं, मध्य वर्ग के परिवारों में भी कई खाद्य पदार्थ या तो गायब हो गए हैं, या उनका उपभोग काफी कम हो गया। फलतः संप्रग सरकार की घोर विफलता के कारण आज करोड़ों भारतीय खाद्य संकट से जूझ रहे हैं।

संप्रग सरकार के इन चार वर्षों में खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य जरूरी वस्तुएं मसलन–वस्त्र, आवास, परिवहन, दवाएं आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगी होती शिक्षा का अर्थ यह है कि लाखों गरीब व मध्य वर्ग के नौजवान अपने बेहतर जीवन जीने के सपने को पूरा नहीं कर सकते। सीमेंट, स्टील की बढ़ती कीमतें के साथ बैंक की उच्च ब्याज दर का मतलब है कि लाखों मध्यवर्गीय परिवार अपना घर होने के सपने को पूरा नहीं कर सकते। भवन निर्माण व विनिर्माण की मंद होती गति ने पहले से ही व्याप्त बेरोजगारी में इजाफा किया है।

मार्च 2008 के अंत में आधिकारिक मुद्रास्फिति का 7.41 प्रतिशत का आंकड़ा, जो तीन वर्षों में सर्वाधिक है, मूल्य वृद्धि के मात्र छोटे हिस्से को दर्शाता है। जिम्मेदार मीडिया के

एक वर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा वास्तविक आंकड़ों से काफी कम है। न तो प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और न ही वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम स्वयं को इस आरोप से मुक्त कर पाए हैं कि सरकार मुद्रास्फिति के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर रही है।

मूल्य नियंत्रण करने में सरकार की विफलता, इसकी असंवेदनशीलता तथा गैर जिम्मेदाराना रवैए के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई। संसद में महंगाई पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने सरकार को छोड़ सबको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मंहगाई को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकिया कहकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने सरकार द्वारा निर्मित इस समस्या की गंभीरता को कम करने की कोशिश की है।

देश ही हालत यह है कि जब आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है तथा खाद्यान्न उनके कय शक्ति से बाहर चली गई है, तब भारतीय समाज के गरीब वर्ग को अपने जीने के अधिकार खतरे में दिखाई दे रहा है। राजग ऐसी अभूतपूर्व स्थिति को लेकर चिंतित है तथा इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। यदि स्थिति नही सुधरी, तब देश में भारी संख्या में कुपोषण व भूख के कारण लोग मरेंगे। कुछ विश्लेषकों ने इस स्थिति को मौन सूनामी की संज्ञा दी है।

वर्तमान स्थिति में व्यापक एवं प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि गरीब भारतीय खाद्यान्न व अन्य मूलभूत जरूरतों का उचित मात्रा में कम मूल्य पर प्राप्त कर सकें। ऐसा करना सरकार की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं इसे आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक मानूगा। संप्रग सरकार गरीबों के प्रति अपने इस दायित्व को निभाने में पूरी तरह विफल रही है।

राजग इस विकराल होती समस्या का विरोध संसद के भीतर और बाहर पूरी शक्ति से करेगी। राजग सांसदों द्वारा आज की यह मानव श्रृंखला हमारे उसी संकल्प को दर्शाती है।